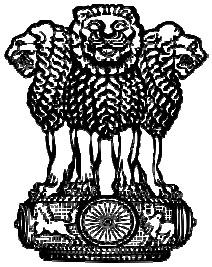

सत्यमेव जयते

# बिहार विधान परिषद्

## 191वां सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

## वर्ग-2

**23 माघ 1940 (श.)**

**मंगलवार, तिथि ----------**

**12 फरवरी, 2019 ई.**

**प्रश्नों की कुल संख्य—14**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वास्थ्य विभाग | --- | --- | --- | 13 |
| 2. | ऊर्जा विभाग | --- | --- | --- | 01 |
| | | | | | ---------- |
| | | | | कुल प्रश्न | 14 |

## मरीजों को राहत

1. **प्रो. नवल किशोर यादव :** क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि इन दिनों पी.एम.सी.एच. में दवाओं की किल्लत बनी हुई है और इसके अतिरिक्त यहां इमरजेंसी और ऑपरेशन थियेटर में भी जरूरी दवाएं यथा बैंडेज, सीरिंज, ग्लब्स तक उपलब्ध नहीं है जिससे मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अस्पताल में दवा नहीं होने के कारण मरीजों के परिजन और चिकित्सकों के बीच अक्सर झड़प एवं कभी-कभी मारपीट तक होती रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतलायेगी कि खंड 'क' एवं 'ख' में वर्णित स्थिति का क्या कारण है और यह कैसे उत्पन्न हो गई है तथा इन अभावों को कबतक पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे मरीजों को राहत मिल सके?

---

## कार्रवाई पर विचार

2. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबन पीएचसी वित्तीय वर्ष 2012-13, 13-14 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये गये विभिन्न कार्यक्रमों में करीब 7 लाख, 50 हजार, 975 रु. पीएचसी के विभिन्न कर्मियों के नाम पर अग्रिम भुगतान किया गया है जिसमें ऐसे व्यक्ति भी जो पीएचसी के कर्मी नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में भी लगभग 15 लाख रु. भी खर्च कर दिया गया जिसका लेखा-जोखा नहीं है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं है बिना रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इतनी बड़ी राशि का खर्च करना संदेहास्पद है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो तत्कालीन प्रभारी डा. सत्यप्रकाश सिंह ने 19 जुलाई, 2017 को सीएस व डीएम को पत्र लिखकर पीएचसी की ऑडिट कराने की गुहार लगाई है, ऑडिट कराई गई है तो इसके फलाफल क्या हैं, अगर नहीं कराई गई है तो सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

## राशि का भुगतान

3. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के खुशरूपुर प्रखंड अंतर्गत पचरुखिया स्वास्थ्य उपकेन्द्र लगभग 25 वर्षों से किराये के मकान में चल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र का किराया मकान मालिक को मात्र 50/-रुपया प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के ज्ञापांक-32734, दिनांक-26.12.11 के द्वारा किराये पर चलने वाले स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराया500/- रुपये प्रतिमाह दिसंबर, 2005 से निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि पचरूखिया स्वास्थ्य उपकेन्द्र के किराये का भुगतान नई दर से जनवरी, 2014 से किया जा रहा है किन्तु दिसंबर, 2005 से दिसंबर, 2013 तक की अवधि का किराया भुगतान अभी तक लंबित है;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पचरुखिया स्वास्थ्य उपकेन्द्र के किराये की बकाया राशि का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

**नियुक्ति पर विचार**

4. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के दंत विभाग में भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदंड के आलोक में सहायक प्राध्यापक के 36 पद रिक्त हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण दंत से संबंधित चिकित्सा के साथ पढ़ाई सुचारु रूप से नहीं हो रही है, जिस कारण आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जनहित में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सहायक प्राध्यापक दंत की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

---

**दवा उपलब्ध**

5. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2020 तक कालाजार व 2025 तक टीबी से मुक्त करने का सरकार का लक्ष्य है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में कालाजार व टीबी के अभी तक कितने मरीज हैं;

(ग) क्या यह सही है कि कालाजार से सर्वाधिक आक्रांत है, राज्य सरकार वर्ष में दो बार दवा का छिड़काव कर रही है, वर्ष 2018 में कहां-कहां दवा का छिड़काव हुआ है, प्रत्येक मरीज को मुफ्त दवा के अतिरिक्त नगद रुपये भी दिये जाते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि कालाजार और टीबी की दवा सभी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है जिसके कारण मरीजों को कठिनाई उठानी पड़ रही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक ग्रामीण अस्पताल के साथ सभी अस्पताल में कालाजार और टीबी की दवा उपलब्ध करना चाहती है ?

---

**एम्बुलेंस की व्यवस्था**

6. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकारी एम्बुलेंस 10 रुपये प्रति मिलोमीटर की दर पर उपलब्ध है, सरकारी एम्बुलेंस पर नियंत्रण रखने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक सेल बना हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में निजी एम्बुलेंस मरीजों से मनमाफिक किराया लेते हैं और निजी एम्बुलेंस की निगरानी के लिए अभी तक राज्य में कोई रेगुलेशन नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि निजी एम्बुलेंस का निबंधन भी एम्बुलेंस के रूप में नहीं है जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के मरीजों को कम खर्च और निर्धारित दर पर एम्बुलेंस मिले इसके लिए निजी एम्बुलेंस पर नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेशन बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

**कारगर कदम**

7. **श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा :** क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना सहित राज्य के अनेक भागों में धड़ल्ले से निजी अस्पताल, क्लीनिक खुले हैं जहां मरीजों से इलाज के नाम पर धन उगाही एवं भयादोहन किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि आये दिन इन निजी अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार एवं मार-पीट की घटनाएं घटित होती रहती हैं साथ ही ऐसे अस्पतालों में मरीजों को इलाज के नाम पर धड़ल्ले से उन्हें आई. सी.यू. में पहले भर्ती कराया जाता है फिर उन्हें वेंटीलेटर पर डाल कर भारी मात्रा में पैसे की उगाही की जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि इन अस्पतालों में डाक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफों से ज्यादा बांउसरों एवं हॉकी स्टिक, लोहे के रॉड, डंडे पाये जाते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि इन अस्पतालों से निकलने वाले कचड़ों को नष्ट नहीं कर खुले में ही फेंक दिया जाता है;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाने एवं कोई नियमावली बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**पदस्थापन की व्यवस्था**

8. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिले में सिविल सर्जन, ए.सी.एम.ओ. तथा सदर अस्पताल के अधीक्षक का पद रिक्त रहने के कारण ये तीनों पद प्रभार में चल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इन तीनों पदों का प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी को बनाया गया है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**ट्रांसफार्मर हटाने पर विचार**

9. **श्री सोनेलाल मेहता** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि खगिडया नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नं.-13, उत्तरी हाजीपुर, प्राथमिक विद्यालय, वार्ड नं.-01, के सामने पूर्व से सड़क पर ही पोल के बीच ट्रांसफार्मर लगा हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित पोल से चार पहिया वाहन के टकराने से ट्रांसफार्मर में आग लगने और उस आग की लपेट में आने से अबतक तीन लोगों की मौत हो गई है;

(ग) क्या यह सही है कि स्थानीय लोगों ने पोल पर फ्लैक्सों लगाकर संकेत दिया है कि 'यह ट्रांसफार्मर खुली है' सावधान रहें;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित पोल एवं ट्रांसफार्मर हटाकर दूसरे स्थान पर लगवाना चाहती है, हां तो कबतक?

---

**स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण**

10. **श्री टुनजी पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिला के दरौली प्रखंड अंतर्गत नेतवार गांव के अगल-बगल कोई प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि ग्रामीण इलाका होने के कारण देहात के गरीब लोगों को इलाज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार नेतवार में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलना चाहती है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्या स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

---

## स्वास्थ्य सुविधा

11. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा पटना के स्लम एरिया के आस-पास गर्दनीबाग, शास्त्रीनगर, रूकनपुरा, पच्छिम लोहानीपुर, संदलपुर कुम्हरार, कौशलनगर और दीघा मुहसहरी में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया;

(ख) क्या यह सही है कि इन स्वास्थ्य केन्द्रों में पीएचसी जैसी जांच की सुविधा नहीं है एवं बाहर से दवाई खरीदनी पड़ती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो उक्त केन्द्रों पर गरीब मरीजों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधा नहीं मिलने का क्या कारण है?

---

## मानदेय का भुगतान

12. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना सचिवालय कर्मियों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए नया सचिवालय (विकास भवन) स्थित परिसर में राजकीय औषधालय है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मौजूदा अस्पताल में पूर्व कर्मियों के लिए रक्त जांच, एक्स-रे एवं अन्य प्राथमिक जांच की सुविधाएं थीं, किन्तु इसमें कार्यरत लैब कर्मियों (तकनीशियनों) को मानदेय राशि का भुगतान नहीं करने से वे लैब कार्य छोड़कर भागने के लिए विवश हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडोंके उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त स्थिति में लैब कर्मियों को मानदेय राशि का भुगतान करने एवं पूर्व की भांति रक्त सहित अन्य जांच का संचालन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

## ब्लड बैंक की स्थापना

13. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 39 ब्लड बैंक कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अरवल, अररिया, बांका, शिवहर, सुपौल, गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर, सदर अस्पताल, भागलपुर और अनुमंडलीय अस्पताल, बेनीपुर, दरभंगा में ब्लड बैंक खुलने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह सही है कि बक्सर जिला अन्तर्गत डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में अल्ट्रा साउंड मशीन और ब्लड बैंक नहीं है जिसके कारण रोगियों को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में अल्ट्रा साउंड और ब्लड बैंक की स्थापना करना चाहती है ?

---

## नियमित भत्ता नहीं

14. **श्री टुनजी पाण्डेय :** क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य भर में आशा कार्यकर्ता सभी पंचायतों में कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इनको कोई नियमित भत्ता नहीं मिलता है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को एक हजार रुपया प्रतिमाह देने के लिए कहा गया था;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आशा कर्मियों को 1000 रु. प्रतिमाह देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**विनोद कुमार**

कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक-12 फरवरी, 2019